

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 17 जुलाई, 2017

विषय:-

नाबार्ड की RIDF-XXII के अन्तर्गत वित्त पोषित जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड भटवाड़ी की किशनपुर बहुल ग्राम पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक सहायक महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड), उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, 113/2, राजपुर रोड, देहरादून के पत्र संख्या: राबैं, उत्तराखण्ड/ 1945/ एडी (एलओएस) -15 /2016-17 दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 एवं अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 1204/XXVII(1)/2016 दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 व आपके पत्र संख्या: 1308/अप्रेजल-उत्तरकाशी/36 दिनांक 27 अगस्त, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड की RIDF-XXII के अन्तर्गत वित्त पोषित जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड भटवाड़ी की किशनपुर बहुल ग्राम पम्पिंग पेयजल योजना अनुमानित लागत ₹ 770.84 लाख पर व्यय वित्त समिति द्वारा परीक्षणों परान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 630.47 लाख (छ: करोड़ तीस लाख सैतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना हेतु नाबार्ड द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी ₹ 201.321 लाख (दो करोड़ एक लाख बत्तीस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018, तक पूर्ण, उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भौति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- (viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा

नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (x) व्यय वित्त समिति द्वारा योजना की सम्पूर्ण लागत का अनुमोदन किया गया है। इसे दरों एवं मात्राओं का अनुमोदन न समझा जाय।
- (xi) कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात् कोई भी आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
- (xii) निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।
- (xiii) आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0/उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन निर्माण निगम की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मर्दे एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपहरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मर्दों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपहरिहार्य मर्दे हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति -98-नाबार्ड वित्त पोषित-9801-नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान (4215-01-102-05से स्थान्तरित)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 1707130677 दिनांक 13 जुलाई, 2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 संख्या-224/XXVII (2)/2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)  
अपर सचिव।

पू0सं0 255 (1)/उन्तीस(2)/17-2(129 पे0)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, 113/2, राजपुर रोड, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(महावीर/सिंह चौहान)  
संयुक्त सचिव।

(3) आधार पर वर्गीकृत किया जाये और वहाँ पर उपयुक्त का नंबर आमतौर पर का जाय।  
क्या किये गये माल, जैसा कि नियम 46 के उपनिधम (2) में वर्गीकृत किया गया हो, के सम्बन्ध में उक्त रूपरेखा में  
लेखे अलग-अलग रहे जाये।